

कंसोर्टियम ऑफ टीटागढ़ फायरमा एडलर एस.पी.ए. - टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, टीटागढ़
टावर्स, 756, आनंदपुर, ई.एम. बाईपास, कोलकाता- 700107, पश्चिम बंगाल अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से,

बनाम

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एनएमआरसीएल), मुख्य कार्यालय मेट्रो हाउस, बंगला
नं. 28/2, आनंद नगर, सी.के. नायडू रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर अपने महाप्रबंधक
(खरीद) और अन्य के माध्यम से।

(सिविल अपील क्रमांक 1353-1354/2017)

मई 09, 2017

[दीपक मिश्रा और अमिताव रॉय, जे.जे.]

अनुबंध:

अनुबंध का अवार्ड - सरकारी निकाय द्वारा (प्रतिवादी संख्या 1) - पीपुल्स रिपब्लिक
ऑफ चाइना सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी (प्रतिवादी संख्या 2) को अपीलकर्ता-
कंपनी से प्राथमिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि प्रतिवादी नंबर 2 कंपनी
तकनीकी रूप से योग्य नहीं थी क्योंकि उसकी बोली 'एकल इकाई' की नहीं थी और
उसने अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव पर भरोसा किया था -माना गया: प्रतिवादी
नंबर 2 एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसकी सहायक कंपनियों का मालिक था और
'सरकारी स्वामित्व वाली इकाई' के रूप में बोली दस्तावेज़ के सीएल.4.1 के दायरे में
आता था - प्रतिवादी संख्या 1 ने समझ और व्याख्या में अपने वाणिज्यिक ज्ञान का
उपयोग किया, जिसे संबंधित समिति और फाइनेंसिंग बैंक द्वारा सहमति दी गई है -

किसी भी विकृति, पूर्वाग्रह या दुर्भावना के अभाव में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में प्रतिवादी द्वारा रखी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायिक समीक्षा:

संविदात्मक मामलों के संबंध में प्रशासनिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा - का दायरा - अभिनिर्धारित: संविदात्मक मामलों के संबंध में सरकारी निकायों के प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानी या पक्षपात को रोकना है और इसे व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाता है - प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने के लिए विशेषज्ञता का अभाव है - प्रशासनिक निर्णय को न केवल वेडनसबरी सिद्धांत या तर्कसंगतता के अनुप्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, बल्कि पूर्वाग्रह से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानी से भी मुक्त होना चाहिए - यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और सार्वजनिक हित में, अदालतें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही मूल्यांकन में कोई प्रक्रियात्मक टिप्पणी या त्रुटि हो या किसी निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह हो - वर्तमान मामले के तथ्यों में, किसी भी विकृति, पूर्वाग्रह या दुर्भावना के अभाव में प्रश्नगत अनुबंध देने के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. हालांकि जहां तक सरकारी निकायों की संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग का सवाल है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य मनमानी या पक्षपात को रोकना है और इसका प्रयोग व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाता है या यदि यह अदालत के ध्यान में लाया जाता है कि अनुबंध देने के मामले में किसी अतिरिक्त उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रशासनिक

कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण होना चाहिए. कोर्ट की भूमिका सिर्फ यह समीक्षा करना है कि फैसला किस तरीके से लिया गया है. प्रशासनिक निर्णय को सही करने के लिए न्यायालय के पास विशेषज्ञता का अभाव है। सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जो प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए आवश्यक सहवर्ती के रूप में जोड़ों में निष्पक्ष खेल को मान्यता देती है। प्रशासनिक निर्णय को न केवल तर्कसंगतता के वेडनसबरी सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, बल्कि पूर्वाग्रह से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानी से भी मुक्त होना चाहिए। यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और सार्वजनिक हित में है, तो अदालतें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही कोई प्रक्रियात्मक विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह हो। [पैरा 27,29] [359-सी-ई; 361-एफ-जी]

टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651:
[1994] 2 पूरक एससीआर 122; मॉटेकार्लो लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड 2016 (10) स्केल 50; जगदीश मण्डा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (2007) 14 एससीसी 517: [2006] 10 पूरक एससीआर 606; मास्टर मरीन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम मेटकाफ एंड हॉजकिंसन (पी) लिमिटेड और अन्य (2005) 6 एससीसी 138: (2005) 3 एससीआर 666; बी.एस.एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य (2006) 11 एससीसी 548: [2006] 8 पूरक एससीआर 11; मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड कर्नाटक राज्य (2012) 8 एससीसी 216: (2012] 8 एससीआर 128; ए/कंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2016 (8) स्केल 765; तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैजेडको) प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और

एक अन्य बनाम सीएसईपीडीएल-ट्रिंशे कंसोर्टियम, इसके प्रबंध निदेशक और एक अन्य द्वारा प्रतिनिधि 2016 (10) स्केल 69; रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और दूसरा 2017 (1) स्केल 453; एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ट्राफलगर हाउस कंस्ट्रक्शन (आई) लिमिटेड और अन्य (1997) 1 एससीसी 738: (1996] 10 सप्लिमेंट एससीआर 209 - पर भरोसा किया गया।

2.1 प्रतिवादी संख्या 2 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्वामित्व वाली कंपनी है और इसलिए, यह सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में बोली दस्तावेज़ के खंड 4.1 के दायरे में आती है। जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने माना है, एक एकल इकाई अपने लिए बोली लगा सकती है और इसमें उसके घटक शामिल हो सकते हैं जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं और उनके पास परियोजना के संबंध में अनुभव हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि उक्त प्रतिवादी द्वारा समझा गया है, जहां एकल या एकीकृत इकाई का दावा है कि विलय के परिणामस्वरूप, सभी सहायक कंपनियां अधिकारों, देनदारियों, परिसंपत्तियों और दायित्वों के संबंध में उसके तत्काल नियंत्रण में एक समरूप पूल बनाती हैं, ऐसे अधिकारों, संपत्तियों और देनदारियों के मालिक के रूप में एकल इकाई की अखंडता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। दूसरे प्रतिवादी की पात्रता मानदंड का निर्णय करते समय, पहले प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 164 को स्कैन किया है जो कि बोली के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 2 के निदेशक मंडल को सहायक कंपनियों के लिए भी सभी आवश्यक और आवश्यक निर्णयों और कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले प्रतिवादी के अनुसार, "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" शब्द में एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई और उसकी सहायक कंपनियां शामिल होंगी और इसमें कोई संदेह नहीं हो

सकता है कि संस्थाओं की पहचान सरकार से संबंधित है। स्थापित होने पर इसे सरकारी स्वामित्व वाली इकाई माना जा सकता है और सहायक कंपनियों के मूल द्वारा दावा किए गए अनुभव को ध्यान में रखा जा सकता है। [पैरा 32) [363-जी-एच; 364-ए-डी)

2.2 इस प्रकार, रिकॉर्ड पर सामग्री है कि प्रतिवादी नंबर 2, एक सरकारी कंपनी, सहायक कंपनियों का मालिक है और सहायक कंपनियों के पास अनुभव है। प्रथम प्रतिवादी ने समझ और व्याख्या में अपने व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग किया है जिसे संबंधित समिति और वित्तपोषण बैंक द्वारा सहमति दी गई है। "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" की अवधारणा को एक संकीर्ण संरचना प्रदान नहीं की जा सकती। इसमें मालिक की संतुष्टि के अधीन इसकी सहायक कंपनियां शामिल होंगी। किसी संयुक्त उद्यम या कंसोर्टियम के गठन की आवश्यकता नहीं है। तथ्य प्राप्त करने की स्थिति में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, किसी भी प्रकार की विकृति, पूर्वाग्रह या द्वेष की अनुपस्थिति में प्रथम प्रतिवादी द्वारा रखी गई व्याख्या में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम प्रतिवादी द्वारा लिया गया निर्णय व्यावसायिक ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह किसी भी तरह से सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है। (पैरा 34) (366-डी-जी)

न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1995) 1 एससीसी 478: [1994] 5 पूरक एससीआर 310; यूपी राज्य वी. रेनूसागर पावर कंपनी (1988) 4 एससीसी 59: [1988] 1 पूरक एससीआर 627 - पर निर्भर। डब्ल्यू.बी. बिजली बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 451: [2001] 1 एससीआर 352; लिटिलवुड्स मेल ऑर्डर स्टोर्स, लिमिटेड बनाम मैक ग्रेगर (1969) 3 सभी ईआर 855; डीएचएन फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड और अन्य बनाम लंदन बरो ऑफ़

टॉवर हैमलेट्स (1976) 3 ए आई आर 462; हेरोल्ड होल्ड्सवर्थ एंड कंपनी (वेक.फील्ड) लिमिटेड वी. कैंडीज़ (1955) 1 डब्लूएलआर 352; सेंट्रल कोल.फील्ड्स लिमिटेड बनाम एसएलएल-एसएमएल (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम (2016) 8 एससीसी 622; बा/वंत राय सलूजा और अन्य बनाम एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य (2014) 9 एससीसी 407; रोहडे और श्वार्ज़ जीएमबीएच एंड कंपनी केजी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (2014) 207 डीएलटी 1; क्योर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य 2011 (59) बीएलजेआर 183; श्रीमती बाचा एफ गुज़दार, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे एआईआर 1955 एससी 74: [1955) एससीआर 876; भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कोर्ट्स लिमिटेड और अन्य (1986) 1 एससीसी 264: [1985) 3 पूरक एससीआर 909; वेस्टर्न ए कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोरबा और अन्य (1982) 1 एससीसी 125: [1982) 2 एससीआर 1; नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर एआईआर' 1936 पीसी 253 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[1994) 5 पूरक एससीआर 310	निर्भर	पैरा 4
[1994) 2 पूरक एससीआर 122	निर्भर	पैरा 4
(2016) 8 धारा 622	संदर्भित	पैरा 4
2016 (8) स्केल 765	निर्भर	पैरा 4
(2014) 9 धारा 407	संदर्भित	पैरा 11

(2014) 207 डीएलटी 1	संदर्भित	पैरा 11
2011 (59) बीएलजेआर 183	संदर्भित	पैरा 11
[1988) 1 पूरक एससीआर 627	निर्भर	पैरा 12
2016 (10) स्केल 50	निर्भर	पैरा 13
[2012) 8 एससीआर 128	निर्भर	पैरा 13
[2006) 10 पूरक एससीआर 606	निर्भर	पैरा 13
[1955) एससीआर 876	संदर्भित	पैरा 15
[1985) 3 पूरक एससीआर 909	संदर्भित	पैरा 26
[1982] 2 एससीआर 1	संदर्भित	पैरा 26
एआईआर 1936 पीसी 253	संदर्भित	पैरा 26
[2005] 3 एससीआर 666	निर्भर	पैरा 27
[2006] 8 पूरक एससीआर 11	निर्भर	पैरा 27
2016 (10) स्केल 69	निर्भर	पैरा 28
2017 (1) स्केल 453	निर्भर	पैरा 29
[1996] 10 पूरक एससीआर 209	निर्भर	पैरा 29
[2001) 1 एससीआर 352	संदर्भित	पैरा 30
(1969) 3 सभी ईआर 855	संदर्भित	पैरा 32

(1976) 3 एआईआर 462

संदर्भित

पैरा 32

(1955) 1 डब्ल्यूएलआर 352

संदर्भित

पैरा 32

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1353-1354/2017

डब्ल्यूपी (सी) नंबर 5818/2016 और एमसीए (समीक्षा) नंबर 1087/2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले और आदेश दिनांक 05.10.2016 और 22.11.2016 से।

साथ

सिविल अपील संख्या 1355/2017.

डॉ. ए.एम. सिंह vi, राजू रामचन्द्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सौरभ किरपाल, प्रदीप अग्रवाल, दीपक विश्वास, निशित मिश्रा, अर्जुन मिनोचा, सौरव विग, सुश्री अनन्या घोष, धनंजय मिश्रा, अर्नव दाश रामेन्द्र मोहन पटनायक - अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

मुकुल रोहतगी, एजी, गोपाल सुब्रमण्यम, ध्रुव मेहता, एस.के. मिश्रा, श्याम दीवान, वरिष्ठ वकील, मेहुल एम. गुप्ता, पवन भूषण, आर. पी. गुप्ता, प्रभजीत जौहर, सुश्री अनुम्पा के, एन. पी. सिंह, एस.एस. जौहर - उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला **न्यायाधीश दीपक मिश्रा** द्वारा सुनाया गया।

1. नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां प्रथम प्रतिवादी, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना में 69 यात्री रोलिंग स्टॉक (इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट) के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण, कमीशनिंग और कर्मियों के प्रशिक्षण के काम के लिए 25.01.2016 को निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया। उक्त परियोजना को KfW डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। बोली मूल्यांकन और

अनुबंध के सभी चरणों में खंड ITS 35.8 के अनुसार, अवार्ड केएफडब्ल्यू विकास बैंक से अनापत्ति के अधीन होना होगा।

2. उक्त एनआईटी के जवाब में, तीन बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। एक को तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया और इस प्रकार, केवल अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 ही प्रतियोगिता में बचे रहे। 29.09.2016 को वित्तीय बोली खोलने पर यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने 852 करोड़ रुपये की बोली दी थी जबकि प्रतिवादी नंबर 2 की बोली 851 करोड़ रुपये थी। प्रतिवादी की निदेशक स्तर की निविदा समिति ने निविदा मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की और प्रतिवादी नंबर 2 की सबसे कम पेशकश को स्वीकार करने की सिफारिश की और कुछ तकनीकी आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद कार्य आदेश जारी किया जाना था। कार्य आदेश जारी करने से पहले, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की रिट याचिका संख्या 5818 दायर की और तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 तकनीकी रूप से योग्य नहीं थी और इसलिए, इसकी वित्तीय बोली नहीं खोली जा सकती थी।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निविदा दस्तावेज़ का खंड 26 किसी व्यक्ति को अनुबंध दिए जाने तक प्रतिस्पर्धी की तकनीकी योग्यता के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने से रोकता है, जो मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है; कि प्रतिवादी नंबर 2 के पास एनआईटी के तहत आवश्यक अपेक्षित अनुभव नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, लेकिन अपनी सहायक कंपनी के अनुभव पर निर्भर था।

4. डिवीजन बेंच ने खंड 26 की वैधता या अन्यथा पर जाने के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने यह अच्छी तरह से जानते हुए भी निविदा बोली में भाग लिया था कि ऐसा खंड मौजूद था और उसके लिए यह तर्क देना संभव नहीं था कि उक्त खंड कठिन है और इसमें पारदर्शिता का अभाव है और इसलिए,

यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है; और उसने इसे तभी चुनौती दी थी जब यह पाया गया कि उसकी वित्तीय बोली प्रतिवादी नंबर 2 की तुलना में अधिक थी। यह आगे देखा गया कि अगर अपीलकर्ता होता तो मामला अलग होता। निविदा सूचना प्रकाशित होने के तुरंत बाद, एनआईटी जारी होने के बाद उक्त शर्त को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया¹, टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया⁰, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एसएलएल-एसएमएल (ज्वाइंट वेंचर सीओ11सोर्टियम)³ और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड⁴ के फैसलों पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। ध्यान दें, हालांकि उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि वह रिट याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर गैर-अनुकूलित कर सकता था कि उसने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि खंड 26.1 की प्रकृति में शर्त मौजूद थी, फिर भी विवाद को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। और मालिक को निर्देश दिया कि वह केवल इस बात से संतुष्ट होने के लिए रिकॉर्ड पेश करे कि नियोक्ता/मालिक द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध है या नहीं और आगे यह जांचने के लिए कि क्या मालिक ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवादी नंबर 2, सबसे कम बोली लगाने वाले के पास अपेक्षित अनुभव है। रिकॉर्ड पर मौजूद सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि:-

"15. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा मूल्यांकन समिति में मुख्य परियोजना प्रबंधक/आरएस, महाप्रबंधक/खरीद, मुख्य परियोजना प्रबंधक/सिग्नलिंग और महाप्रबंधक/वित्त शामिल हैं। उक्त समिति ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2 की तकनीकी योग्यता के संबंध में दस्तावेजों का मूल्यांकन किया है। समिति ने कहा है कि प्रतिवादी नंबर 2 का गठन जून 2015 में सीआरसी कॉर्पोरेशन और सीएनआर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विलय से हुआ था। विलय से संबंधित

दस्तावेज बोली के साथ जमा किये गये हैं. मूल्यांकन समिति ने यह भी नोट किया है कि प्रतिवादी नंबर 2 के निगमन के बाद, सीएसआर कॉर्पोरेशन और सीएनआर कॉर्पोरेशन के विलय पर, प्रतिवादी नंबर 2 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नाएडा मेट्रो परियोजना के लिए 76 कारों की आपूर्ति का ठेका दिया गया था। समिति ने पाया कि जहां तक खंड संख्या 12 का संबंध है, हालांकि न्यूनतम आवश्यकता यह थी कि बोली लगाने वाले के पास कुल 60 मेट्रो कारों का अनुभव होना चाहिए और जिनमें से 30 कारें या तो स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम होनी चाहिए, प्रतिवादी नंबर 2 के पास कुल 594 मेट्रो कारों का अनुभव था और सभी कारें स्टेनलेस स्टील की थीं। जहां तक खंड 12.1 का संबंध है, जिसके लिए आवश्यक है कि निर्मित कारों की संख्या में से, मूल/निर्माता के देश के बाहर कम से कम एक देश में या भारत में या 30 मेट्रो कारों में से जीएस देश में कम से कम एक में संतोषजनक राजस्व संचालन पूरा किया जाना चाहिए, प्रतिवादी नंबर 2 को मूल देश के बाहर 432 का अनुभव था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज के अवलोकन से पता चलेगा कि तकनीकी मूल्यांकन समिति की निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रासंगिक कारकों द्वारा निर्देशित की गई है और यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी भी प्रासंगिक कारक पर विचार नहीं किया है . इसलिए, हमारा मानना है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय 'तर्कसंगतता' के दायरे में आएगा।

16. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा मूल्यांकन समिति के कार्यवृत्त को निदेशक स्तर की निविदा समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया था जिसमें निदेशक (रोलिंग स्टॉक और सिस्टम),

निदेशक (परियोजनाएं) और निदेशक (वित्त) शामिल थे। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मामले की जांच केवल विशेषज्ञ समिति के एक स्तर पर नहीं की गई है, बल्कि विशेषज्ञों के दो स्तरों पर जांच की गई है।"

5. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने यहां पहले उल्लिखित अधिकारियों का उल्लेख किया और उनमें बताए गए सिद्धांतों की सराहना की और अंततः रिट याचिका को खारिज कर दिया।

6. यह उल्लेख करना उचित है कि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुबंध के अवार्ड के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। हालाँकि, न्यायालय ने रिट याचिका वापस लेने की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मांगी गई स्वतंत्रता देने के लिए इच्छुक नहीं थी। सरलता से वापसी को स्वीकार नहीं किया गया और स्वतंत्रता देने पर जोर दिया गया। उक्त तथ्य से निपटते हुए, डिवीजन बेंच ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सुप्रा) के एक अंश का उल्लेख किया और इस प्रकार व्यक्त किया: -

"24. हमने पाया है कि यदि हम याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, तो यह याचिकाकर्ता को फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और परियोजना में और देरी करने का मौका देगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए, हमने स्वयं निविदा मूल्यांकन समिति और निदेशक स्तर समिति के संपूर्ण मिनटों की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा निर्धारित परीक्षण का जवाब देती है या नहीं। हमने पाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को मनमानी, तर्कहीनता या

दुर्भावना के आधार पर दूषित नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुरोध को स्वीकार करने से परियोजना में और देरी होगी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह परियोजना नागपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हालाँकि जो प्रार्थना पहली नज़र में अहानिकर प्रतीत होती है, उसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है।"

7. रिट याचिका खारिज होने के बाद, समीक्षा के लिए एक आवेदन (एम.सी.ए. [समीक्षा] संख्या 1087/2016) दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने समीक्षा के लिए आवेदन पर विचार करते समय उन दो आधारों पर गौर किया जिन पर समीक्षा की मांग की गई थी। यह पुनः प्रस्तुत करने लायक है:-

"i. वेडनसबरी तर्कसंगतता के सिद्धांत का प्रयोग करते समय, समीक्षा में आदेश जांच की प्रक्रिया में प्रासंगिक चूक को ध्यान में रखने में विफल रहा, जैसे

(ए) दर में छूट कैसे नहीं दी जा सकती और

(बी) सेवा कर की अनुचित गणना जिससे आवेदक की बोली सबसे कम हो जाती है।

ii. प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अधिकारियों के समक्ष प्रासंगिक तथ्यों को दबाया गया था।"

8. उक्त पहलू से निपटते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा: -

"13. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.जी. अणे ने प्रस्तुत किया कि जब कोई कार्रवाई कानून में दुर्भावना

के दायरे में आती हैं, तो उन व्यक्तियों को पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल करना आवश्यक नहीं हो सकता है जिनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया गया है। हम पाते हैं कि किसी भी तरह से वर्तमान मामला कानून में दुर्भावना के दायरे में नहीं आएगा। यदि यह आवेदक का मामला है कि निविदा प्रसंस्करण अधिकारियों ने प्रतिवादी नंबर 2 का पक्ष लेने के लिए जानबूझकर कुछ चूक की है या प्रतिवादी नंबर 2 को अनुबंध प्राप्त करने में मदद करने के लिए कुछ दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है, तब उस घटना में प्रतिवादी नंबर 1 के ऐसे अधिकारी, जिन्हें ऐसे कृत्य या चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, आवश्यक पक्ष थे। इसलिए याचिकाकर्ता के लिए उन व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट दावे करना भी आवश्यक था। जैसा कि यहां पहले ही चर्चा की जा चुकी है, हालांकि उस संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न किया गया था, उस स्तर पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा कि याचिका के ज्ञापन में ऐसी किसी भी दुर्भावना को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इस तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, इस आधार पर समीक्षा की मांग की गई कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा मूल्य बोलियों का गलत जानबूझकर मूल्यांकन किया गया था और वही कार्य प्रतिवादी नंबर 2 का पक्ष लेने और याचिकाकर्ता को अवैध रूप से बाहर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण था। हमारी दृष्टि में यह ड्राफ्ट्समैन के उर्वर मस्तिष्क की कल्पना है।

14. हम आगे पाते हैं कि समीक्षा एप्लिकेशन दिमाग के पूर्ण गैर-प्रयोग को दर्शाता है। आवेदन के पैराग्राफ संख्या 6.8 में, समीक्षा आवेदन के ड्राफ्ट्समैन ने कहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई जेवी/कंसोर्टियम नहीं बनाया है और इस तरह, वह निविदा प्रक्रिया में बोली लगाने के

लिए पात्र नहीं था। हमें उम्मीद है कि समीक्षा आवेदन का ड्राफ्ट्समैन एक संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम और दो कंपनियों के एक में विलय के बाद एक नई कंपनी के निगमन के बीच बुनियादी अंतर को समझता है।

15. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि याचिका का ज्ञापन 22 पृष्ठों का है, समीक्षा आवेदन 39 पृष्ठों का है। हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि समीक्षा आवेदन बिना दिमाग लगाए तैयार किया गया है। नियमों के अनुसार समीक्षा आवेदन दाखिल करते समय एक वकील को यह प्रमाणित करना चाहिए कि आदेश की समीक्षा की मांग करने के लिए अच्छे आधार मौजूद हैं। हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वर्तमान मामले में उक्त प्रमाणीकरण बहुत ही अनौपचारिक तरीके से किया गया है, केवल नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन दिखाने के लिए।"

9. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय ने 1 लाख रुपये (एक लाख रुपये) की लागत के साथ समीक्षा के लिए आवेदन खारिज कर दिया।

10. हमने सिविल अपील संख्या 1353-1354/2017 में अपीलकर्ता के विद्वान वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सुश्री अनन्या घोष के विद्वान वकील को सुना है। श्री राजू रामचन्द्रन, श्री रामेन्द्र मोहन पटनायक के विद्वान वरिष्ठ वकील, सिविल अपील संख्या 1355/2017 में अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील, श्री मुकुल रोहतगी, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, श्री आर.पी. गुप्ता के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, श्री श्याम दीवान, श्री एस.एस. जौहर के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील।

11. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की बचाव क्षमता पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 2 की बोली 'एकल इकाई' की नहीं है और उसने अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव पर भरोसा किया था; कि उसने बोली अपने अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि पूर्ववर्ती मूल/मूल कंपनियों की सहायक कंपनियों के अनुभव के आधार पर प्रस्तुत की है, जिनके विलय के बाद प्रतिवादी नंबर 2 अस्तित्व में आया था, जो न केवल पात्रता और योग्यता मानदंडों के विपरीत है, बल्कि कानून की तय स्थिति के भी विपरीत है, जो यह प्रावधान करता है कि जब तक सहायक कंपनियां संयुक्त उद्यम (जेवी) की घटक न हों, होल्डिंग कंपनी के अनुभव पर विचार करने के उद्देश्य से उनके अनुभव को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है; कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास, एकल आधार पर, निविदा शर्तों के तहत प्रदान किया गया अपेक्षित अनुभव नहीं है; प्रतिवादी नंबर 2 को अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए अपनी बोली या तो एक संयुक्त उद्यम के रूप में या अपनी सहायक कंपनियों के साथ एक संघ के रूप में देनी चाहिए थी; कि बोली लगाने वाले पर कंसोर्टियम या जेवी बनाए बिना अपनी सहायक कंपनियों, जो अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, का अनुभव लेने के लिए एक विशिष्ट प्रतिबंध है; प्रतिवादी नंबर 2 की सहायक कंपनियां अलग और स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं हैं और जिन आपूर्तियों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अनुभव का दावा किया गया है, वे आपूर्ति प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा नहीं बल्कि अन्य स्वतंत्र कानूनी संस्थाओं द्वारा की गई थीं; प्रतिवादी नंबर 2 के पास कार बॉडी के निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं और उसे अपनी सहायक कंपनियों को इसका उप-अनुबंध देना होगा, जो अनुबंध की निविदा शर्तों के खंड 4.4 का उल्लंघन है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बलवंत राय सलूजा और एनोटलजर बनाम एयर इंडिया लिमिटेड और ओटल्टर्स 5, रॉल्टडे और श्वार्ज़ गमहली एंड कंपनी के.जी. बनाम एयरपोर्ट

अथॉरिटी ऑफ इंडिया⁶ और कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य 7 पर भरोसा जताया है।

12. प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दलीलें रखने से पहले तथ्यों को सामने रखा और प्रचारित किया कि परियोजना को KfW डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित किया गया था और खंड IB 35.8 के अनुसार, बोली मूल्यांकन और अनुबंध अवार्ड के सभी चरणों को KfW की अनापत्ति के अधीन होना होगा: अपीलकर्ता ने प्रथम प्रतिवादी को पत्र लिखकर अनुबंध III-ए (पीक्यू-एलनिशियल फिल्टर) के खंड 12.1 में संशोधन की मांग की, यानी "ऑपरेशन प्रदर्शन" खंड जिसके अनुसार, जैसा कि तब था, बोली लगाने वाले को कम से कम 30 मेट्रो कारों को निर्माण के देश के बाहर या भारत में वितरित किया जाना चाहिए और इस शर्त को शामिल करने की मांग की गई कि जी 8 देशों में से किसी को भी डिलीवरी को स्वीकार्य माना जाना चाहिए; कि अपीलकर्ता का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और वह बोली लगाने के योग्य हो गया; कि प्रथम प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के अनुरोध पर निविदा जमा करने की तिथि 14 जून से बढ़ाकर 24 जून कर दी; कि सभी बोली दस्तावेज़ प्रीक्वालिफिकेशन (पीक्यू) और तकनीकी अनुमोदन के लिए प्रथम प्रतिवादी के स्वतंत्र जनरल कंसल्टेंट को दिए गए थे, जिसमें मिस.सिस्ट्रा, मिस.राइट्स, मिस.एईसीओएम और मिस.एजिस शामिल थे, जिसने प्रतिवादी नंबर 2 को योग्य माना और प्रथम प्रतिवादी की मूल्यांकन और निविदा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी, जिसे 29.8.2016 को क्रेडीटब्ल्यू जर्मनी को उसकी अनापत्ति के लिए भेज दिया गया; महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई-पोर्टल पर लगाई गई बोलियां 29.9.2016 को खोली गईं और प्रतिवादी नंबर 2 की बोली सबसे कम 851 करोड़ रुपये पाई गई जबकि अपीलकर्ता की बोली 852 करोड़ रुपये थी; 29.9.2016 और 3.10.2016 को अपीलकर्ता ने प्रथम प्रतिवादी को यह कहते हुए अभ्यावेदन दिया कि प्रतिवादी नंबर 2 एक होल्डिंग कंपनी के रूप में योग्य नहीं था और एक सहायक कंपनी के अनुभव के लाभ का दावा

नहीं कर सकता था और उसने अपने अनुभव के मुकाबले प्रतिवादी नंबर 2 की पात्रता से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी; और 4.10.2016 को अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के तकनीकी दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति नहीं दी गई थी, खंड 25.1 और 25.3 का पालन नहीं किया गया था, बोली-मूल्य अपीलकर्ता के इतना करीब होने के कारण इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए था और मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में निविदा देना दुर्भावनापूर्ण था, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.10.2016 के आदेश के तहत यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि बोली का मूल्यांकन उचित था और अपीलकर्ता खंड 26 को चुनौती नहीं दे सका, जिसमें अनुबंध दिए जाने तक तकनीकी बोलियों की गोपनीयता अनिवार्य थी।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देंगे कि प्रतिवादी नंबर 2, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, यह स्पष्ट रूप से 'सरकारी स्वामित्व वाली इकाई' के रूप में बोली-दस्तावेज के खंड 4.1 के दायरे में आती है। विद्वान वरिष्ठ वकील आग्रह करेंगे कि एक एकल इकाई अपने लिए बोली लगा सकती है और इसमें उसके घटक शामिल हो सकते हैं जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं और उनके पास परियोजना के संबंध में अनुभव हो सकता है और सभी सहायक कंपनियां अधिकारों, देनदारियों, परिसंपत्तियों और दायित्वों के संबंध में इसके तत्काल नियंत्रण के तहत एक समरूप पूल बनाती हैं, जो प्रतिवादी संख्या 2 के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुच्छेद 164 के मद्देनजर है, इसके निदेशक मंडल को सहायक कंपनियों के लिए सभी आवश्यक निर्णय और कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई है और, इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अनुभव को मूल कंपनी के अनुभव का हिस्सा माना जाना चाहिए; और यह कि 'सरकारी स्वामित्व वाली इकाई' शब्द में सरकारी

स्वामित्व वाली इकाई और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ कोई रोक शामिल नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कॉर्पोरेट घूँघट हटाने के सिद्धांत के इतिहास का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया, इस न्यायालय ने कॉर्पोरेट घूँघट को हटाने वाले सिद्धांतों में ढील दी है और यूपी राज्य बनाम रेनूसागर पावर कंपनी 8 और न्यू होरिज़ॉन्ट लिमिटेड (सुप्रा) के अधिकारियों पर भरोसा किया है। श्री गोपाल सुब्रमण्यम आगे यह तर्क देंगे कि बोली दस्तावेजों की प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से जांच की गई है और यह सफल बोली लगाने वाले, यानी प्रतिवादी नंबर 2 की क्षमता, अनुभव और विशेषज्ञता से संतुष्ट है। प्रतिवादी नंबर 2 की तकनीकी योग्यता का गहन विश्लेषण स्वतंत्र जनरल कंसल्टेंट की रिपोर्ट से स्पष्ट है; कि दुनिया भर में मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति में प्रतिवादी नंबर 2 का अनुभव अपीलकर्ता के अनुभव से काफी अधिक है; प्रतिवादी संख्या 2 को उसकी 100% सहायक कंपनियों के साथ एक इकाई के रूप में मानना इस तथ्य से समर्थित है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके पास समान, यदि समान नहीं, शब्दयुक्त बोली-दस्तावेज़ है, ने प्रतिवादी संख्या 2 को निविदा प्रदान की है।, जिसने 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से अनुभव और निष्पादन का दावा करते हुए एक मूल कंपनी के रूप में वहां बोली लगाई थी; कि निविदा दस्तावेज़ में मूल कंपनी के साथ-साथ उसकी 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को एक इकाई के रूप में मानने पर किसी भी प्रकार की, व्यक्त या निहित, कोई रोक नहीं है; बोली दस्तावेज़ की योजना ऐसी है जो स्वयं प्रावधान करती है कि सहायक कंपनी के विफल होने की स्थिति में मूल कंपनी को समझौते के तहत कार्य करना होगा और इसके मद्देनजर, अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां अति-तकनीकी हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय ने लगातार माना है कि अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल तभी होती है जब मालिक द्वारा लिया गया निर्णय तर्कहीन या मनमाना हो, या पूर्वाग्रह, पक्षपात या दुर्भावना से प्रेरित हो। उन्होंने मॉंटेकार्लो लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड, मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम

कर्नाटक राज्य, जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सुप्रा) में अधिकारियों पर भरोसा किया है।

14. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने, एक सरकारी संस्था होने के नाते, निविदा में भाग लिया और सभी विवरण दिए, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया। और प्रतिवादी नंबर 2 और उसकी 00% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों द्वारा निष्पादित विभिन्न अनुबंधों की आपूर्ति और कमीशनिंग के संपूर्ण विवरण की जांच करने के बाद अनुबंध को निष्पादित करने के लिए उसके पक्ष में दिनांक 5.10.2016 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि वर्तमान निविदा में अपने अनुभव के प्रयोजनों के लिए, प्रतिवादी नंबर 2 ने फॉर्म 4.4 संलग्नक- 1 में इस आशय का विवरण प्रदान किया था कि इसने पिछले 10 वर्षों में 606 मेट्रो कारों की आपूर्ति की है जो अपीलकर्ता के अनुभव से कहीं अधिक है जो परियोजना के लिए फायदेमंद होगा और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएगा। श्री दीवान ने प्रतिवादी संख्या 2 के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 164 पर दृढ़ता से भरोसा किया, जो बोली के साथ प्रस्तुत किया गया था, और तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 2 के निदेशक मंडल को सहायक कंपनियों सहित कंपनी के लिए निर्णय लेने का पूरा अधिकार सौंपा गया है और इसलिए, जब तक इकाई एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है, इसमें मूल और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां दोनों शामिल होनी चाहिए।

15. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दी गई दलीलों के जवाब में, 2017 की सिविल अपील संख्या 1353-1354 में अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी ने कहा कि खंड 4.1 एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई को किसी अन्य बोलीदाता की तरह मानता है। और इसे कोई रियायत या तरजीही व्यवहार नहीं देता है

और यदि कोई कंपनी बोली जमा करने के उद्देश्य से अपनी सहायक कंपनियों को शामिल नहीं कर सकती है और उनके अनुभव को अपने अनुभव के रूप में नहीं गिन सकती है (संघ/जेवी बनाए बिना), यही मानदंड सरकारी स्वामित्व वाली इकाई पर भी लागू होता है। उन्होंने आगे अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड आईटीबी 43, 43.1 से 43.4, 39.3, 42.1, 42.2 और खंड 1.14 का उल्लेख किया और कहा कि काम सौंपने के मामले में, डिफॉल्ट की स्थिति में प्रस्तावित जेवी/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों पर संयुक्त और कई जिम्मेदारी और दायित्व तय किए जाने चाहिए और यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसा उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रतिवादी नंबर 2, एक एकल इकाई के रूप में अपनी बोली लगाने के बाद, अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव पर भरोसा करने और गुप्त रूप से शामिल करने का हकदार है और ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नंबर 2 या सहायक कंपनियों पर जिम्मेदारी और दायित्व डालना असंभव होगा। इसकी सहायक कंपनियां निविदा दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों में चूक करती हैं। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 22.6.2016 की आलोचना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पत्र 1" प्रतिवादी के लिए एक तरफा संचार है और कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौते का गठन नहीं करता है और निविदा दस्तावेजों के तहत निर्धारित प्रारूपों के पालन के अभाव में, ऐसे पत्र की कोई पवित्रता नहीं है और इसे प्रतिवादी नंबर 2 और उसकी सहायक कंपनियों के बीच कानूनी रूप से वैध और बाध्यकारी समझौते के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पत्र में गलत तरीके से कहा गया है। इसकी सहायक कंपनियों का अनुभव मूल कंपनी का अनुभव है क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास केवल अपनी सहायक कंपनियों के शेयर होते हैं और शेयरों के मालिक होने का मतलब यह नहीं है कि होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की संपत्ति, देनदारियों और अनुभव की मालिक है और श्रीमती बाचा एफ. गुजदार, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे'2 पर निर्भर है।

16. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देंगे कि प्रतिवादी नंबर 2 ने अपनी छह सहायक कंपनियों के अनुभव और प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा नामित इकाई को अपने दायरे में सीमित करने की कोशिश की है। चूंकि वर्तमान निविदा के तहत काम पूरा करने के लिए जिम्मेदार इकाई यानी एमआईएस.सीआरआरसी डालियान कंपनी लिमिटेड के पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है, जबकि शेष पांच संस्थाओं/सहायक कंपनियों के पास पूर्व अनुभव हो सकता है; देय सेवा कर में गंभीर और स्पष्ट अंकगणितीय त्रुटि है जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की बोली 32.82 करोड़ रुपये से कम है; सिंगापुर और हांगकांग में उनकी सहायक कंपनियों द्वारा दोषपूर्ण मेट्रो कारों की आपूर्ति के संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा गंभीर भौतिक तथ्यों को छुपाया गया है, जिसे वापस लेना पड़ा और फिलीपींस में रिश्वत के भुगतान का आरोप लगाया गया है। ये खुलासे निविदा दस्तावेजों के अनुलग्नक के अनुसार किए जाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रतिवादी को निविदा प्रक्रिया से प्रतिवादी नंबर 2 को अयोग्य घोषित करने की आवश्यकता होती।

17. बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए एनआईटी की कुछ प्रासंगिक शर्तों की सराहना की जानी आवश्यक है। खंड 4.1 पात्रता मानदंड से संबंधित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"4.1 एक बोली लगाने वाला एक फर्म हो सकता है जो एक निजी इकाई, एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है - टीबी 4.3 के अधीन - या किसी मौजूदा समझौते के तहत संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में ऐसी संस्थाओं का कोई संयोजन हो सकता है या आशय पत्र द्वारा समर्थित ऐसे समझौते में प्रवेश करने के इरादे से। संयुक्त उद्यम के मामले में, ॥ सदस्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे। जेवी एक

प्रतिनिधि को नामांकित करेगा जिसके पास बोली प्रक्रिया के दौरान और जेवी को अनुबंध दिए जाने की स्थिति में, अनुबंध निष्पादन के दौरान जेवी के किसी भी और सभी सदस्यों के लिए और उनकी ओर से सभी व्यवसाय संचालित करने का अधिकार होगा। जब तक बीओएस में निर्दिष्ट न हो, जेवी में सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

4.3 बोली लगाने के लिए एजेंसी के पात्रता मानदंड अनुभाग V में वर्णित हैं - पात्रता मानदंड और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी।"

18. खंड 4.1 पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त खंड में सन्निहित शर्तें स्पष्ट रूप से एक संघ या संयुक्त उद्यम की स्थिति अर्जित करने के लिए पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को निर्धारित करती हैं और उक्त अभिधारणाएं ऐसे बोली लगाने वाले, जो "एकल इकाई" है और एक बोली लगाने वाला, जो एक संघ या एक संयुक्त उद्यम है, द्वारा पूरा किए जाने वाले दायित्वों, जिम्मेदारियों आदि के संबंध में अंतर प्रदान करता है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, हमारा ध्यान खंड 4.7.4.8 और 4.11 की ओर आकर्षित किया गया है। हमें खंड 11.3.1.3, 11.3.1.4, 11.3.1.9, 12.2 और 43.3 का अवलोकन करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है।

19. खंड 12 और 12.1 प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"12. डिलिवरी रिकार्ड

क्या बोली लगाने वाले/संघ/अपने सदस्यों के संयुक्त उद्यम को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अन्य संघ/संयुक्त उद्यम के सदस्य के रूप में वाहन डिजाइन, इंटरफ़ेस (सिग्नलिंग, ट्रैक, ट्रैक्शन इत्यादि जैसे अन्य नामित ठेकेदारों के साथ) का अनुभव है और कार्यान्वित किया

गया है। पिछले दस (10) वर्षों में न्यूनतम कुल 60 मेट्रो (यानी एमआरटी, एलआरटी, उपनगरीय रेलवे या हाई स्पीड रेलवे) कारों की असेंबली और आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग, जिनमें से न्यूनतम 30 कारें या तो स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम होंगी।

12.1. ऑपरेशन प्रदर्शन

उपरोक्त एसएन 12 के अनुसार कमीशन की गई 60 या अधिक कारों में से कम से कम 30 मेट्रो (यानी एमआरटी, एलआरटी, उपनगरीय रेलवे या हाई स्पीड रेलवे) कारों ने संतोषजनक राजस्व संचालन पूरा किया है।

* मूल/निर्माण के देश के बाहर कम से कम एक देश में।

* या भारत में

* या पिछले तीन (3) वर्षों में कम से कम एक G8 देश अर्थात् कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में।"

20. धारा V पात्रता मानदंड और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

"सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम या संस्थान वाले बोलीदाता केवल तभी भाग ले सकते हैं यदि वे यह स्थापित कर सकें कि वे (i) कानूनी और वित्तीय रूप से स्वायत्त हैं (ii) वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं। पात्र होने के लिए, एक सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम या संस्थान अपने चार्टर और एजेंसी द्वारा अनुरोध की जा सकने वाली अन्य जानकारी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के माध्यम से एजेंसी की

संतुष्टि के अनुसार स्थापित करेगा कि वह: (i) उनकी सरकार से अलग एक कानूनी इकाई है (ii) वर्तमान में पर्याप्त सब्सिडी या बजट समर्थन प्राप्त नहीं होता है; (iii) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम की तरह संचालित होता है, और, अन्य बातों के अलावा, अपने अधिशेष को अपनी सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है, अधिकार और देनदारियां प्राप्त कर सकता है, धन उधार ले सकता है और अपने ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी हो सकता है, और दिवालिया घोषित किया जा सकता है।"

21. खंड 27 जो बोलियों के स्पष्टीकरण से संबंधित है और खंड 29 जो प्रतिक्रियाशीलता के निर्धारण से संबंधित है, प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"27. बोलियों का स्पष्टीकरण

27.1 बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना और बोलीदाताओं की योग्यता में सहायता के लिए, नियोक्ता अपने विवेक से, प्रतिक्रिया के लिए उचित समय दिए जाने पर, किसी भी बोली लगाने वाले से उसकी बोली के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। किसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो नियोक्ता के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए नियोक्ता का अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी। आईटीबी 31 के अनुसार, बोलियों के मूल्यांकन में नियोक्ता द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा, बोली की कीमतों या सामग्री में किसी भी स्वैच्छिक वृद्धि या कमी सहित कोई बदलाव की मांग, पेशकश या अनुमति नहीं दी जाएगी।

27.2 यदि कोई बोलीदाता नियोक्ता के स्पष्टीकरण अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी बोली का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जा सकती है।

29. उत्तरदायित्व का निर्धारण

29.1 नियोक्ता द्वारा बोली की प्रतिक्रिया का निर्धारण बोली की सामग्री पर ही आधारित होना चाहिए, जैसा कि आईटीबी 11 में परिभाषित किया गया है।

29.1.1 सामान्य मूल्यांकन: बोलियों के विस्तृत मूल्यांकन से पहले, नियोक्ता यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक बोली:

- उचित रूप से हस्ताक्षरित किया गया है; और
- एक वैध बोली सुरक्षा के साथ होना चाहिए; और
- योग्यता (प्रारंभिक फ़िल्टर) मूल्यांकन मानदंड को पूरा करता है - नियोक्ता इन दस्तावेजों में दर्शाए गए प्रारंभिक फ़िल्टर मानदंडों के आधार पर पात्रता और स्वीकार्यता का मूल्यांकन करेगा। केवल उन्हीं बोलीदाताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा, जो प्रारंभिक फ़िल्टर मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करेंगे।
- सत्यनिष्ठा, पात्रता और सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के विवरण की हस्ताक्षरित प्रति। उपरोक्त में से किसी भी आइटम का 'नहीं' उत्तर बोली/बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर देगा।

29.1.2 तकनीकी पैकेज का मूल्यांकन: नियोक्ता केवल ऐसे बोलीदाताओं की कार्य आवश्यकताओं - सामान्य विशिष्टताओं और तकनीकी

विशिष्टताओं के अनुसार तकनीकी उपयुक्तता और स्वीकार्यता निर्धारित करने के लिए तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा जो उपरोक्त बीओएस आईटीबी 29.1.1 के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं।

बीओएस आईटीबी पैरा 11.3.1 (इसके प्रासंगिक उप-पैरा सहित) के अनुसार प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन पैरा 2, अनुभाग वीआईएल-ए और VII-बी के अनुसार सामान्य और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए किया जाएगा। साथ ही भाग, अनुबंध IV-सी में दिए गए मापदंडों के विपरीत। इसके अलावा, भाग I में संबंधित आवश्यकताओं के लिए बोलीदाता की प्रतिक्रियाओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा।

29.2 एक पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियाशील बोली वह है जो सामग्री विचलन, आरक्षण या चूक के बिना बोली दस्तावेजों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। भौतिक विचलन, आरक्षण, या चूक वह है जो,

(ए) यदि स्वीकार किया जाता है, तो होगा:

(i) अनुबंध में निर्दिष्ट कार्यों के दायरे, गुणवत्ता या प्रदर्शन को किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करना; या

(ii) प्रस्तावित अनुबंध के तहत बोली दस्तावेजों, नियोक्ता के अधिकारों या बोली लगाने वाले के दायित्वों के साथ असंगत किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से सीमा; या

(बी) यदि सुधार किया गया, तो पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियाशील बोलियां प्रस्तुत करने वाले अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धी स्थिति पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा।

29.2.1 योग्यता शर्तों का मूल्यांकन: ऐसी बोलियाँ जिनमें योग्यताएँ शामिल हैं:

1. बोली दस्तावेजों में ठेकेदार को आवंटित जोखिम और/या दायित्व का पूरा या कुछ हिस्सा नियोक्ता, किसी अन्य सरकारी एजेंसी या किसी अन्य ठेकेदार को स्थानांतरित करने का प्रयास करना; या

2. जिसमें बोली दस्तावेजों से विचलन शामिल है जो कार्यो, या उसके किसी भी हिस्से को उनके इच्छित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त बना देगा; या

3. "(ए) आवेदकों का फ़िल्टर - प्रारंभिक फ़िल्टर मूल्यांकन मानदंड की चेकलिस्ट" के एसएन 12, 12.1 और 13 में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने में विफल रहता है; या

4. जो धारा IX के तहत मुख्य तिथियों 6 और 9 के तहत निर्दिष्ट कार्यो को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तिथि को प्रतिबद्ध करने में विफल रहता है। विशेष शर्तें (पीसी) भाग ए - अनुबंध डेटा 'तालिका: अनुभागों का सारांश' को गैर-अनुरूपण माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

29.3 नियोक्ता आईटीबी 16 के अनुसार प्रस्तुत बोली के तकनीकी पहलुओं की जांच करेगा, विशेष रूप से, यह पुष्टि करने के लिए कि धारा VII, कार्य आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं को बिना किसी भौतिक विचलन, आरक्षण या चूक के पूरा किया गया है।

29.4 बोलियाँ जो हैं:

- उपरोक्त आईटीबी 29.1.1 के अनुसार सामान्य मूल्यांकन मानदंड को पूरा नहीं करना,
- उपरोक्त आईटीबी 29.2 के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं है
- उपरोक्त आईटीबी 29.2 के अनुसार भौतिक विचलन या आरक्षण होना
- उपरोक्त आईटीबी 29.2.1 के अनुसार अर्हता शर्तों को पूरा नहीं करना, और
- नियोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना -

उपरोक्त आईटीबी 29.1.2 के अनुसार सामान्य विशिष्टता और तकनीकी विशिष्टता को गैर-अनुरूपण माना जाएगा और नियोक्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, और बाद में गैर-अनुरूप विचलन या आरक्षण को सुधार या वापस लेने के द्वारा उत्तरदायी बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

29.5 यदि कोई भी बोली उपरोक्त आईटीबी 29.4 के अनुसार खारिज कर दी जाती है, तो ऐसे बोलीदाता का वित्तीय पैकेज बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

29.6 बोलीदाता ध्यान दें कि उपरोक्त आईटीबी 29.4 के अनुसार 'प्रारंभिक फ़िल्टर मूल्यांकन मानदंड' और 'तकनीकी मूल्यांकन' में उनकी योग्यता के अनुसार, यदि बोलीदाता (संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के मामले में प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य पर लागू होता है) को बोली जमा करने की नियत तारीख के बाद लेकिन एनएमआरसीएल द्वारा वित्तीय पैकेज

खोलने से पहले भारत सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में डाल दिया जाता है, वे इस तरह के प्रतिबंध के जारी होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर एनएमआरसीएल को लिखित रूप में इसकी सूचना देंगे, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने जानबूझकर जानकारी छिपाई है और बोलीदाता इस बोली की शर्तों के अनुसार उत्पन्न होने वाले सभी प्रभावों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ऐसी किसी भी रोक के परिणामस्वरूप बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और ऐसे बोलीदाता का वित्तीय पैकेज बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।"

22. जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी तकनीकी प्रस्ताव के खंड 4.11 पर जोर दिया है, हम सोचते हैं कि उक्त खंड के प्रासंगिक भाग को निकालना उचित है: -

"1. बोली लगाने वाले की संरचना से संबंधित कंसोर्टियम समझौते की एक नोटरीकृत प्रति प्रस्तुत की जाएगी, यदि बोली लगाने वाला एक संघ है। क्या बोली लगाने वाले को इस अनुबंध के लिए बोली लगाने के लिए स्थापित या स्थापित इकाई होना चाहिए, शेयरधारकों के समझौते या प्रस्तावित शेयरधारकों के समझौते का विवरण समझौतों में प्रतिशत भागीदारी और प्रतिशत इक्विटी के साथ प्रदान किया जाएगा।

2. संविदात्मक व्यवस्था और उसके संबंध में समझौतों की प्रतियों में, कम से कम, शामिल सभी सदस्यों या प्रतिभागियों, बोली में उनकी संबंधित भागीदारी, प्रबंधन संरचना, बोली लगाने वाले सदस्यों या प्रतिभागियों के स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। प्रमुख सदस्य का नाम, जिसके पास कार्यों के लिए समग्र नेतृत्व प्रबंधन जिम्मेदारी होगी, सभी पक्षों के पंजीकृत पते और उनके

संबंधित वरिष्ठ भागीदारों, अध्यक्षों या प्रबंध निदेशकों के नाम, जैसा उचित हो। इस तरह के समझौतों में नियोक्ता के प्रति सदस्यों की संयुक्त और कई देनदारियों को भी दर्शाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अनुबंध दिया जा सके और उस स्थिति में "गतिरोध" प्रावधान प्रदान किए जाएं, जब कंसोर्टियम के निर्णय सर्वसम्मत समझौते से नहीं हो सकते।"

23. जैसा कि अज्ञात तथ्यों से पता चलेगा, 17.02.2016 को 357 अपीलकर्ता ने प्रतिवादी 1 को पत्र लिखकर "ऑपरेशन प्रदर्शन खंड" में संशोधन की मांग की, यानी, अनुबंध III-ए (पीक्यू-एलनिशियल फ़िल्टर) के खंड 12.1 के अनुसार। उक्त खंड के अनुसार, बोली लगाने वाले को निर्माण के देश के बाहर या भारत में वितरित की गई कम से कम 30 मेट्रो कारों को संतोषजनक ढंग से वितरित करना आवश्यक है, जिस संशोधन की मांग की गई थी वह इस शर्त को शामिल करने से संबंधित था कि जीएस देशों में से किसी को भी डिलीवरी को स्वीकार्य माना जाना चाहिए। ऐसा संशोधन अपीलकर्ता की विलय की गई इकाई के लिए था, जिसने उसे अपेक्षित अनुभव दिया था, जिसने केवल जीएस देशों में मेट्रो कारों का निर्माण और वितरण किया था। अपीलकर्ता के अनुरोध को नियोक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया और G8 देशों में से किसी को भी आपूर्ति को अनुमेय के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा, बोली लगाने के लिए समय बढ़ाने की अपील करने वाले अपीलकर्ता के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार समय बढ़ाया गया और जमा करने की अंतिम तिथि 08.07.2016 घोषित की गई। जो समय शाम 4 बजे तय किया गया था. शाम 7 बजे तक बढ़ाया गया। अपीलकर्ता के अनुरोध पर. इन पहलुओं को बताने का मकसद सिर्फ यह उजागर करना है कि बदनीयती के आरोप सच्चाई से कोसों दूर हैं।

24. जैसा कि हम समझते हैं, मुख्य मुद्दा "प्रतिवादी" द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की तकनीकी बोली की स्वीकृति से संबंधित है और हमें आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखते हुए पात्रता मानदंड की कसौटी पर ही इसे संबोधित करना आवश्यक है। अन्य तकनीकी पहलुओं पर निर्णय, जैसा कि हमें वर्तमान में सलाह दी जाती है, विशेषज्ञों पर छोड़ देना बेहतर है। हमारा उक्त डोमेन में प्रवेश करने का इरादा नहीं है, हालांकि उक्त संबंध में एक कमजोर प्रयास किया गया है।

25. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत दलील यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 वास्तव में पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, लेकिन 1 प्रतिवादी ने, कुछ अथाह कारणों से, जानबूझकर इस तथ्य पर अपनी आँखें बंद कर ली हैं जो कि प्रक्षेपित किया गया है और दूसरे प्रतिवादी को चतुराई से एकल इकाई का दर्जा प्रदान किया गया।

26. इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 को एक इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता था और, किसी भी मामले में, वह अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का दावा नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी सहायक कंपनियों के साथ कोई कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम नहीं बनाया गया था। होल्डिंग और सहायक कंपनियों के संबंध के संबंध में, हमें बा/वंत राय सलूजा (सुप्रा) में अधिकारियों की सराहना की गई है और रोलटेड और श्वार्ज़ .जीएमबीएच एंड कंपनी केजी में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की भी सराहना की गई है। (सुप्रा)। आवश्यक दलील यह है कि प्रतिवादी नंबर 2, अपनी संपत्तियों और देनदारियों सहित सहायक कंपनियों के मालिक के रूप में, अपने अनुभव का दावा नहीं कर सकता है और "कॉर्पोरेट घूँघट उठाने" के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है, जैसा कि रेनूसागर पावर कंपनी (सुप्रा) और भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य 13 में निर्धारित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि

सरकार के स्वामित्व वाली इकाई के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के स्वामित्व वाली इकाई सरकार से अलग है और, उक्त उद्देश्य के लिए, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोरबा और अन्य 14 में प्राधिकरण से प्रेरणा ली गई है। . यह भी आग्रह किया गया है कि जब निविदा में किसी विशेष कार्य को करने की आवश्यकता होती है, तो इसे उस विशिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून में परिकल्पना की गई है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित कार्य करने की शक्ति दी गई है। काम उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सुप्रा) में प्राधिकरण से प्रेरणा ली गई है, जिसमें नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर 15 पर भरोसा रखा गया है।

27. इससे पहले कि हम एकल इकाई की अवधारणा और "प्रतिवादी" द्वारा उपयोग किए गए विवेक से निपटने के लिए आगे बढ़ें, हम न्यायालय की भूमिका से निपटने का इरादा रखते हैं जब पात्रता मानदंड को न्यायालय द्वारा स्कैन और माना जाना आवश्यक होता है। मॉटेकार्लो लिमिटेड में (सुप्रा), न्यायालय ने टाटा सेल्युलर (सुप्रा) का उल्लेख किया जिसमें कुछ सिद्धांत, अर्थात् आधुनिक प्रवृत्ति, प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक संयम की ओर इशारा करते हैं; न्यायालय की भूमिका केवल उस तरीके की समीक्षा करना है जिसमें निर्णय लिया गया है; प्रशासनिक निर्णय को सही करने के लिए न्यायालय की ओर से विशेषज्ञता की कमी; सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता प्रदान करना, जो प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में जोड़ों में निष्पक्ष खेल को मान्यता देता है, निर्धारित किए गए थे। उक्त मामले में यह भी कहा गया था कि प्रशासनिक निर्णय को न केवल तर्कसंगतता के वेडनसबरी सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, बल्कि पूर्वाग्रह से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानी से भी मुक्त होना चाहिए। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि

जगदीश मंडल (सुप्रा) में यह माना गया है कि, यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और सार्वजनिक हित में है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगी। , भले ही कोई प्रक्रियात्मक विपथन या मूल्यांकन में त्रुटि या किसी निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो, तब भी हस्तक्षेप करें। मास्टर मरीन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम मेटकाफ एंड हॉजकिंसन (पी) लिमिटेड और ए11अन्य16 में निर्णय, बी.एस.एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और ओट्लज़र्स 17 और मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा) का उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने अल्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सुप्रा) के एक अंश का हवाला दिया, जिसमें व्याख्या का सिद्धांत निविदा आवश्यकताओं की सराहना करने और मालिक या नियोक्ता द्वारा दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए रखा गया है, जब तक कि समझ या प्रशंसा में दुर्भावनापूर्ण या विकृत न हो, परिलक्षित होता है। संवैधानिक न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उक्त मामले में यह भी देखा गया है कि यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों की ऐसी व्याख्या दे सकता है जो संवैधानिक न्यायालयों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह अपने आप में दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है। उक्त प्राधिकारी को संदर्भित करने के बाद, यह इस प्रकार तय किया गया है:

"24. हम सम्मानपूर्वक कानून के उपरोक्त कथन से सहमत हैं। हमारे पास ऐसा करने के कारण हैं। वर्तमान परिदृश्य में, निविदाएं जारी की जाती हैं और अत्यधिक जटिल तकनीकी विषयों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए काम की प्रकृति की समझ और सराहना की आवश्यकता होती है और यह जिस उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक क्षेत्र में यह सामान्य ज्ञान है कि निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के अनुसार तकनीकी बोलियों की जांच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और कभी-कभी मालिक के

संगठन से असंबद्ध लोगों से तीसरे पक्ष की सहायता ली जाती है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। बोली लगाने वाले की विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता और क्षमता का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन के मामलों में सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तकनीकी क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता की जांच और पुष्टि करना व्यावहारिक और यथार्थवादी है। एक बहुआयामी जटिल दृष्टिकोण है; प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी। जिन निविदाओं में सार्वजनिक उदारता को नीलामी के लिए रखा जाता है, वे एक अलग डिब्बे में खड़ी होती हैं। जिस निविदा से हमारा संबंध है, वह आवंटन की किसी भी योजना से तुलनीय नहीं है। यह क्षेत्र, जिसका हमने उल्लेख किया है, तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। लागू किए गए पैरामीटर भिन्न हैं। इसका उद्देश्य निष्पादन और समय-सारणी के अनुपालन में उच्च स्तर की पूर्णता प्राप्त करना है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि ये निविदाएं न्यायिक समीक्षा की जांच से बच जाएंगी। यदि दृष्टिकोण मनमाना या दुर्भावनापूर्ण है या अपनाई गई प्रक्रिया किसी का पक्ष लेने के लिए है तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग आवश्यक होगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि उक्त विकृतियों को दूर रखा गया है, लेकिन जहां कोई निर्णय लिया जाता है जो स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज़ की भाषा के अनुरूप होता है या उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए निविदा जारी की जाती है, न्यायालय को संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। न्यायालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन या तुलना की अनुमति नहीं होगी। अन्य क्षेत्रों में अनुबंध से संबंधित एक सामान्य उपकरण को स्कैन करने और समझने के लिए जिस सिद्धांत को लागू

किया जाता है, उसे विशेष कौशल की आवश्यकता वाले तकनीकी कार्यों और परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों की व्याख्या और सराहना करने से अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। मालिक को उद्देश्य पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और जोड़ों में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति होनी चाहिए।"

28. तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TANGEDCO) में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और एक अन्य बनाम सीएसईपीडीआई-ट्रिश् कंसोर्टियम, इसके प्रबंध निदेशक और अन्य 18 के प्रतिनिधि द्वारा, न्यायालय ने, जगदीश मंडल (सुप्रा) का हवाला देने के बाद) और जटिल राजकोषीय मूल्यांकन और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयोजित किया गया:

"36 इस मोड़ पर हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि एक जटिल वित्तीय मूल्यांकन में न्यायालय को संयम के सिद्धांत को लागू करना होगा। कई पहलुओं, खंडों, आकस्मिकताओं आदि को ध्यान में रखना होगा। इन गणनाओं को विशेषज्ञों और उन लोगों पर छोड़ देना बेहतर है जिनके पास इस क्षेत्र का ज्ञान और कौशल है। इसमें शामिल वित्तीय गणना, बोली लगाने वाले की क्षमता और दक्षता और परियोजना को पूरा करने की व्यवहार्यता की धारणा को वित्तीय विशेषज्ञों और सलाहकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतें वास्तव में उक्त दायरे में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। हम वित्तीय सलाहकार के मूल्यांकन पर अपील में नहीं बैठ सकते। यह कहना पर्याप्त है, यह न तो प्रथमदृष्ट्या गलत है और न ही हम इसे विकृत या बेतुका होने के कारण दोषपूर्ण मान सकते हैं।"

29. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 19 में, न्यायालय ने एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ट्राफलगर हाउस कंस्ट्रक्शन (आई) लिमिटेड और अन्य 20 मामले में प्राधिकरण का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया है कि यद्यपि जहां तक सरकारी निकायों की संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य मनमानी या पक्षपात को रोकना है और इसका प्रयोग व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाता है या यदि यह अदालत के ध्यान में लाया जाता है कि अनुबंध देने के मामले में किसी अतिरिक्त उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (सुप्रा) की अदालत ने इस प्रकार कहा:

"75 तत्काल मामले में, हम एनआईए में किसी भी मनमानी या पक्षपात या किसी अतिरिक्त उद्देश्य के लिए शक्ति के प्रयोग को समझने में असमर्थ हैं। इसके अभाव में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं है। मौजूदा मामले में, हमारा मानना है कि राजस्व में वृद्धि और सेवा की सीमा के विस्तार के बाद यह एक विवेकपूर्ण निर्णय है।"

और फिर:

"76. इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भारी वित्तीय प्रभाव वाली जटिल नीलामी प्रक्रिया से संबंधित मामलों में, किसी भी धारणा के आधार पर न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप, जिसे बुद्धिमान माना जाता है या उचित माना जाता है, ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जो उचित नहीं है और अप्रत्याशित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका प्रभाव राजकोषीय असंतुलन की स्थिति पैदा करने की क्षमता वाला हो सकता

है। हमारे विचार में, ऐसी नीलामी में हस्तक्षेप कड़ी जांच के आधार पर होना चाहिए जब एनआईए से शुरू होने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया अंत तक अप्रिय मनमानी या किसी भी बाहरी विचार की बू आती है जो कि बोधगम्य है।"

30. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान डब्ल्यू.बी.इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम पीमेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 2' मामले में प्राधिकरण की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह फैसला सुनाया गया है:

"24 अपीलकर्ता, प्रतिवादी 1 से 4 और प्रतिवादी 10 और 11 सभी आईटीबी से बंधे हैं जिसका ईमानदारी से अनुपालन किया जाना चाहिए। इस प्रकृति और परिमाण के एक कार्य में जहां अकेले पूर्व अर्हता को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, निर्देशों के पालन को पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में ब्रांड करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह भेदभाव, मनमानी और पक्षपात को बढ़ावा देगा और गुंजाइश प्रदान करेगा जो पूरी तरह से कानून के शासन और हमारे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। नियमों/निर्देशों को जारी करने का उद्देश्य उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, ताकि कानून का शासन खतरे में न पड़ जाए। किसी नियम या शर्त में छूट या छूट, जब तक कि जेटीबी के तहत राज्य या उसकी एजेंसियों (अपीलकर्ता) द्वारा एक बोलीदाता के पक्ष में प्रदान नहीं की जाती है, अन्य बोलीदाताओं के मन में उचित संदेह पैदा करेगी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के नियम को खराब कर देगी। और इनाम या दान वितरित करने के मामले में अनुबंध देने के लिए बोली लगाने वाले को चुनने और चुनने में राज्य एजेंसियों की इच्छा के अनुरूप हेरफेर के

लिए जगह प्रदान करें। हमारे विचार में इस तरह के दृष्टिकोण से हमेशा बचना चाहिए। जहां किसी नियम या शर्त को शिथिल करने या माफ करने की शक्ति नियमों के तहत मौजूद है, वहां इसे नियमों के अनुपालन में सख्ती से किया जाना चाहिए। इसलिए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि आईटीबी या नियमों का पालन करना सर्वोत्तम सिद्धांत है, जो सर्वोत्तम सार्वजनिक हित में भी है।

X X X

31 अपीलकर्ता द्वारा शुरू की गई परियोजना निस्संदेह जनता के लाभ के लिए है। परियोजना के कार्य के निष्पादन के तरीके से यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जनहित की सर्वोत्तम सेवा हो। परियोजना के कार्य के निष्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं क्योंकि यह दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है। एक ओर यह उन सभी लोगों को उचित अवसर प्रदान करता है जो कार्य के निष्पादन से संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं और, दूसरी ओर यह अपीलकर्ता को काम की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धियों का चयन करने का विकल्प देता है। सबसे बढ़कर, यह सार्वजनिक कार्यों को पुरस्कृत करने में पक्षपात और भेदभाव को समाप्त करता है; ठेकेदारों के लिए... केवल इसलिए कि एक बोली नियमों और शर्तों के अनुपालन की आवश्यकताओं में सबसे कम है.... "

31. यह कहने के बाद, हमें यह देखना होगा कि निविदा शर्तों की पृष्ठभूमि में प्रतिवादी 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 की पेशकश को कैसे समझा है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन परियोजना को केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी द्वारा वित्त

पोषित किया गया है और क्लॉज आईटीबी 35.8 के अनुसार, यह बोली मूल्यांकन के सभी चरणों में आवश्यक है और अनुबंध अवार्ड केएफडब्ल्यू विकास बैंक की अनापत्ति के अधीन होना चाहिए। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है जिसने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि प्रतिवादी नंबर 2 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा निविदा प्रदान की गई थी। यह भी उजागर किया गया है कि रिपोर्ट के साथ वित्तीय बोली से संबंधित कागजात केएफडब्ल्यू को भेज दिए गए थे, जिसने अपनी अनापत्ति दे दी थी। ज्ञात हो कि, अपीलकर्ता प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में काफी आलोचनात्मक रहे हैं और प्रथम प्रतिवादी ने इसे उचित ठहराने के लिए कई कारण दिए हैं। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, हम केवल पात्रता मानदंड से चिंतित हैं, राजकोषीय पहलू से नहीं।

32. प्रतिवादी संख्या 2. जैसा कि स्पष्ट है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्वामित्व वाली कंपनी है और इसलिए, यह सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में बोली दस्तावेज़ के खंड 4.1 के दायरे में आती है। हमने फैसले के पहले भाग में उक्त खंड को पहले ही पुनः प्रस्तुत कर दिया है। जैसा कि पहले प्रतिवादी ने माना, एक एकल इकाई अपने लिए बोली लगा सकती है और इसमें उसके घटक शामिल हो सकते हैं जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं और उनके पास परियोजना के संबंध में अनुभव हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि उक्त प्रतिवादी द्वारा समझा गया है, जहां एकल या एकीकृत इकाई का दावा है कि विलय के परिणामस्वरूप, सभी सहायक कंपनियां अधिकारों, देनदारियों, परिसंपत्तियों और दायित्वों के संबंध में उसके तत्काल नियंत्रण में एक समरूप पूल बनाती हैं, स्वामित्व के रूप में एकल इकाई की अखंडता। ऐसे अधिकारों, संपत्तियों और देनदारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। दूसरे प्रतिवादी की पात्रता मानदंड का निर्णय करते समय, एल " प्रतिवादी ने प्रतिवादी नंबर 2 के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 164 को स्कैन किया है जो कि बोली के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। यह प्रमाणित है कि

प्रतिवादी नंबर 2 के निदेशक मंडल को सहायक कंपनियों के लिए भी सभी आवश्यक और आवश्यक निर्णयों और कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले प्रतिवादी के अनुसार, "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" शब्द में एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई और उसकी सहायक कंपनियां शामिल होंगी और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संस्थाओं की पहचान सरकार से संबंधित है। स्थापित होने पर इसे सरकारी स्वामित्व वाली इकाई माना जा सकता है और सहायक कंपनियों के मूल द्वारा दावा किए गए अनुभव को ध्यान में रखा जा सकता है। प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान "कॉर्पोरेट घूँघट हटाने" सिद्धांत या "घूँघट छिदवाने" के सिद्धांत की ओर आकर्षित किया है और उस संदर्भ में, लिटिलवुड्स मेल ऑर्डर स्टोर्स लिमिटेड बनाम मैकग्रेगर22, डीएचएन फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड और अन्य बनाम लंदन बरो ऑफ टावर हैमलेट्स23 और हेरोल्ड होल्ड्सवर्थ एंड कंपनी (वेकफील्ड) लिमिटेड बनाम कैडीज24 पर निर्भरता रखी गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने रेनुसागर पावर कंपनी (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांतों पर भी भरोसा किया है, जिन्हें न्यू होराइजन्स लिमिटेड (सुप्रा) में दोहराया गया है। पहले प्रतिवादी की ओर से लिखित लिखित प्रस्तुति में, रेनुसागर पावर कंपनी (सुप्रा) के प्रासंगिक पैराग्राफ प्रचुर मात्रा में उद्धृत किए गए हैं। यह भी आग्रह किया गया है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगम अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करते हैं और इसलिए, ऐसा अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि प्रिंसिपल की पात्रता का संज्ञान न लिया जा सके, जब यह सहायक कंपनियों के अनुभव की बात करता है। श्री सुब्रमण्यम द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि धोखाधड़ी या कानूनी दायित्वों की चोरी के संदर्भ में, "घूँघट छिदवाना" या "कॉर्पोरेट घूँघट उठाना" का सिद्धांत लागू किया जा सकता है लेकिन वर्तमान प्रकृति के किसी मामले में उक्त सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता।

33. पहले प्रतिवादी की संतुष्टि के संबंध में, हमारे सामने यह उजागर किया गया है कि उक्त प्रतिवादी ने बोली दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच की थी और प्रतिवादी नंबर 2 की क्षमता, अनुभव और विशेषज्ञता के बारे में खुद को संतुष्ट किया था और स्वतंत्र जनरल कॉन्सटेंट द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 की तकनीकी योग्यता का गहन विश्लेषण किया गया है और प्रथम प्रतिवादी की मूल्यांकन और निविदा समिति की रिपोर्ट और केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी से अनापत्ति भी प्राप्त हुई है। जो पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। प्रतिवादी संख्या 2 के अनुभव का वर्णन करते हुए, प्रथम प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित निवेदन में कहा गया है:

"36. रिकॉर्ड से यह और भी स्पष्ट है कि सबसे कम बोली लगाने वाला होने के अलावा, दुनिया भर में मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति में आर 2 का अनुभव याचिकाकर्ता के अनुभव से काफी अधिक है, जहां खंड 12 के लिए, आर 2 ने 594 मेट्रो कारों का आंकड़ा दिखाया है, याचिकाकर्ता ने केवल 72 कारों को दिखाया है और खंड 12.1 के लिए जहां आर 2 ने 432 कारों का आंकड़ा दिखाया है, याचिकाकर्ता ने फिर से केवल 72 कारों को दिखाया है। आर 2 का यह विशाल अनुभव परियोजना के लिए फायदेमंद होगा और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएगा।

37. आर 1 ने बिना किसी दुर्भावना या दुर्भावना के आर 2 को अपनी 100% सहायक कंपनियों के साथ एक इकाई के रूप में माना है। खंड की यह समझ दोनों पक्षों अर्थात् आर 1 और आर 2 के अंत में रही है, जो अनुभव का उपयोग करके बोली लगाने और अपनी विभिन्न 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से अनुबंध निष्पादित करने के लिए मूल कंपनी की पात्रता की तुलना में विज्ञापन थे।

38. यह कि अपनी 00% सहायक कंपनियों के साथ आर 2 के उपचार के आर 1 की उपरोक्त समझ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समझ से समर्थित है, जो समान नहीं है, तो समान है, शब्दबद्ध बोली-दस्तावेज़ ने आर 2 को निविदा/समझौता प्रदान किया, जिसने 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से अनुभव और निष्पादन का दावा करने वाली मूल कंपनी के रूप में भी बोली लगाई थी।

39. इसके अलावा, निविदा दस्तावेज़ में मूल कंपनी के साथ-साथ उसकी 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को एक इकाई के रूप में मानने पर कोई रोक नहीं है, चाहे वह व्यक्त या निहित हो। इसलिए, परियोजना और इस प्रकार जनता के सर्वोत्तम हित में आर 1 द्वारा लिए गए निर्णय का निर्णय करने में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होना चाहिए।

40. तर्क है कि आर 1 द्वारा निविदा शर्तों की उपरोक्त समझ से परियोजना या याचिकाकर्ता सहित अन्य बोलीदाताओं को कोई भी परियोजना, जो भी हो, का नुकसान नहीं हुआ है। यह विनमतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि आर 2 ने सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। बोली-दस्तावेज़ में स्वयं एक संघ के रूप में बोली लगाने का प्रावधान था, और ऐसे मामले में किसी भी भौतिक शर्त को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसे पूरा नहीं करने पर किसी भी पक्ष या परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, बोली-दस्तावेज़ की योजना ऐसी है कि यह स्वयं मूल कंपनी गारंटी प्रदान करती है। इस मूल कंपनी गारंटी फॉर्म के अनुसार, सहायक कंपनी के विफल होने की

स्थिति में मूल कंपनी को समझौते के तहत कार्य करना होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां अत्यधिक तकनीकी हैं और केवल परियोजना को असफल पाए जाने के बाद उसे रोकने के लिए उठाई गई हैं।"

34. जैसा कि ध्यान देने योग्य है, रिकॉर्ड पर सामग्री है कि प्रतिवादी नंबर 2, एक सरकारी कंपनी, सहायक कंपनियों का मालिक है और सहायक कंपनियों के पास अनुभव है। जैसा कि प्रतीत होता है, पहले प्रतिवादी ने समझ और व्याख्या में अपने व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग किया है जिसे संबंधित समिति और वित्तपोषण बैंक द्वारा सहमति दी गई है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" की अवधारणा को एक संकीर्ण निर्माण प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसमें मालिक की संतुष्टि के अधीन इसकी सहायक कंपनियां शामिल होंगी। किसी संयुक्त उद्यम या कंसोर्टियम के गठन की आवश्यकता नहीं है। तथ्य प्राप्त करने की स्थिति में, किसी भी प्रकार की विकृति, पूर्वाग्रह या गलत धारणा के अभाव में प्रथम प्रतिवादी द्वारा की गई व्याख्या को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम प्रतिवादी द्वारा लिया गया निर्णय, जैसा कि स्पष्ट है, व्यावसायिक ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह किसी भी तरह से सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार से सहमत हैं।

35. परिणामस्वरूप, अपीलें गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपीलें खारिज

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।